भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय **लोक सभा**

अतारांकित प्रशन सं 1791

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश

1791. श्री दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया है तथा निवेश में प्रतिवर्ष वृद्धि दर कितनी है;
- (ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में स्थापित नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या और सृजित नौकरियों के आंकड़ों के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि पर सरकारी नीतियों और पहलों का क्या प्रभाव पड़ा है;
- (ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की कुल राशि कितनी है तथा इस निवेश में योगदान देने वाले प्रमुख देश कौन से हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए निर्धारित भविष्य की योजनाओं और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है, जिसमें निवेश, रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि के संदर्भ में अपेक्षित परिणाम तथा कोई योजनाबद्ध अंतरराष्ट्रीय सहयोग या समझौते शामिल हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह)

(क): देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), वर्ष 2021-22 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और वर्ष 2020-21 से केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना कार्यान्वित्त कर रहा है। एमओएफपीआई की योजनाओं के तहत इस क्षेत्र में किए गए कुल निवेश और प्रतिशत वृद्धि का विवरण नीचे दिए गए अनुसार है:

पीएमकेएसवाई

परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)							
योजनाएं 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25*							
पीएमकेएसवाई	1875.20	1890.53	2378.12	1729.97	1665.65	732.17	
विकास (%)							

^{*}दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार

॥. पीएमएफएमई

परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)									
योजनाएं	योजनाएं 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25*								
पीएमएफएमई	390.99	2483.14	5198.3	2335.18					
विकास (%)	-	535.09	109.34	-					

^{*} दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार

III. पीएलआईएसएफपीआई

परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)									
योजनाएं 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24									
पीएलआईएसएफपीआई* 663 3106 7067 8910									
विकास (%)	-	368.48	127.53	26.08					

^{*}पीएलआईएसएफपीआई के तहत, सभी लाभार्थियों को 31 मार्च, 2024 से पहले अपनी इकाइयां स्थापित करनी होंगी और वाणिज्यिक परिचालन शुरू करना होगा।

इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	एफडीआई (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
2019-20	904.7
2020-21	393.41
2021-22	709.72
2022-23	895.34
2023-24	608.31
2024-25 (सितंबर 2024 तक)	368.37

(ख): पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई को कार्यान्वित्त करके स्थापित इकाइयों की कुल संख्या क्रमशः 643 और 1,08,580 है। इसके अलावा, पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई के माध्यम से उत्पन्न रोजगार क्रमशः 2,52,025 और 3,78,005 है। वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या								
योजनाएं	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25			
पीएमकेएसवाई	79	106	158	133	117	50			
पीएमएफएमई	-	-	2,885	28,686	54,730	22,279			

रोजगार सृजन							
योजनाओं	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
पीएमकेएसवाई	36600	50204	66760	50618	33581	14262	
पीएमएफएमई - 14201 90188 188802 84814							

पीएलआईएसएफपीआई के तहत, अब तक 213 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है जिससे 289832 लोगों को रोजगार मिला है । इसके अलावा, आंध्र प्रदेश राज्य में इकाइयों की संख्या और सुजित रोजगार इस प्रकार हैं:

योजनाएं	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या	सृजित रोजगार
पीएमकेएसवाई	23	14096
पीएमएफएमई	5770	11185
पीएलआईएसएफपीआई	36	48758

(ग): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	एफडीआई (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
2019-20	904.7
2020-21	393.41
2021-22	709.72
2022-23	895.34
2023-24	608.31
2024-25 (सितंबर 2024 तक)	368.37

इस निवेश में योगदान देने वाले प्रमुख देशों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) को अन्य बातों के साथ-साथ फसलोत्तर नुकसान में कमी लाने, मूल्य संवर्धन बढ़ाने आदि सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए फसलोत्तर अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं का सृजन करने का अधिदेश दिया गया है। मंत्रालय विभिन्न पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास का लक्ष्य रखता है, जिसमें खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना सृजन, और किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने, रोजगार के अवसरों का सृजन करने, अपव्यय को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में मदद करना शामिल है।

एमओएफपीआई ने आत्मनिर्भर भारत पहल के भाग के रूप में कई उपाय किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) शामिल है।

मंत्रालय ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के साथ-साथ नई इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" शुरू की है। यह योजना वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक प्रचालन में है, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के सृजन में सहायता करना तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्ष की अविध में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित्त की जा रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा वर्ष 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित्त की जा रही है, जिसका उद्देश्य फसलोत्तर अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं का सृजन करना है, ताकि फसलोत्तर नुकसान में कमी लाने, मूल्य संवर्धन बढ़ाने आदि सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण/पिररक्षण अवसंरचना की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के अलावा फसलोत्तर नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना भी शामिल है। अब तक पीएमकेएसवाई के तहत 1654 पिरयोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1791 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में देशवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

मिलियन अमेरिकी डॉलर में

	ामालयन अमारका डालर म						
क्रमांक	देश का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (सितंबर 2024 तक)
1	सिंगापुर	202.15	38.80	302.48	267.96	262.44	48.45
2	मॉरीशस	77.18	64.26	82.56	193.90	20.65	41.65
3	यूएसए	68.79	130.91	60.06	66.06	29.51	38.60
4	बेल्जियम	262.39	5.43	24.09	17.70	1.82	2.51
5	फ्रांस	8.71	5.08	66.03	76.75	2.05	4.51
6	स्विट्ज़रलैंड	65.07	11.99	6.50	12.14	50.93	0.19
7	आयरलैंड	-	0.0007	-	-	42.05	83.84
8	मेक्सिको	-	52.28	55.59	5.88	-	9.59
9	ब्रिटिश वर्जीनिया	1.48	1.39	16.12	29.33	71.89	-
10	साइप्रस	106.94	0.28	1.60	-	-	-
11	आईएफएससी, भारत	-	-	-	-	-	104.11
12	जापान	38.26	17.55	3.85	4.22	15.90	7.33
13	नीदरलैंड	9.01	30.83	11.42	25.23	7.07	-
14	ऑस्ट्रेलिया	0.0006	6.42	18.40	0.0003	30.01	20.18
15	ग्वेर्नसे	-	-	-	59.12	5.06	0.86
16	केमन द्वीपसमूह	3.49	5.97	15.02	28.42	6.05	-
17	सऊदी अरब	0.00	0.06	-	47.37	7.98	-
18	संयुक्त अरब अमीरात	7.39	8.27	11.69	6.14	16.11	1.12
19	यूनाइटेड किंगडम	9.37	1.35	10.00	11.70	9.55	0.08
20	इटली	14.58	ı	0.01	0.01	18.17	0.06
21	दक्षिण कोरिया	1.07	0.31	4.50	22.07	2.87	0.49
22	ब्रूनेई दारएस्सलाम	-	-	14.69	11.52	-	-
23	लक्समबर्ग	12.64	-	0.18	0.15	-	0.02
24	थाईलैंड	0.00	0.04	3.02	4.78	0.00001	1.31
25	जर्मनी	4.69	3.32	-	0.51	0.11	0.0007
26	चीन	0.27	6.63	0.22	-	-	-
27	स्पेन	6.05	0.16	0.009	0.08	0.07	0.68
28	इंडोनेशिया	0.11	0.14	0.14	1.87	2.63	0.27
29	कनाडा	0.48	0.69	0.81	0.90	0.88	0.19
30	डेनमार्क	0.51	-		-	2.44	-

	कुल:	904.70	393.41	709.71	895.84	608.31	368.37
61	वर्जिन द्वीप समूह(अमेरिका)	0.0001	-	-	-	-	-
60	कुवैत	0.0007	-	-	-	-	-
59	पोलैंड	-	-	-	-	0.001	-
58	मोरक्को	-	-	-	-	0.008	0.008
57	मिस्र	-	-	-	-	0.03	-
56	लेबनान	-	0.01	0.010	0.009	-	-
55	रोमानिया	-	-	_	0.03	-	-
54	बरमूडा	-	-	0.04	-	-	-
53	जाम्बिया	0.04	-	-	-	-	-
52	दक्षिण अफ़्रीका	0.05	-	-	-	-	-
51	नाइजीरिया	-	-	-	-	0.06	-
50	इजराइल	0.02	-	-	0.02	0.02	0.02
49	कुक आइलैंड	0.04	-	-	0.005	0.04	-
48	लिकटेंस्टाइन **	-	-	-	-	0.11	-
47	अफ़ग़ानिस्तान	-	0.12	-	-	-	-
46	सर्बिया	0.13	-	-	0.001	-	-
45	ग्रीस	-	0.03	0.10	-	-	-
44	ओमान	0.00	0.001	-	0.02	-	0.12
43	बुलारिया	0.08	0.04	0.01	0.01	0.005	-
42	रूस	0.07	0.03	0.001	-	-	0.05
41	आइसलैंड	-	-	0.10	0.07	-	0.14
40	श्रीलंका	0.17	-	-	-	0.15	0.05
39	स्वीडन	-	-	-	0.26	0.12	-
38	कतर	0.07	0.07	0.17	-	0.19	-
37	ट्रिनिडाड और टोबैगो	-	-	-	0.10	0.45	0.04
36	स्वाजीलैंड	-	-	-	-	0.67	-
35	केन्या	0.00	0.68	-	-	-	-
34	ताइवान	1.01	-	-	-	-	-
33	न्यूज़ीलैंड	0.30	-	-	1.25	-	0.006
32	हांगकांग	1.91	0.22	-	0.09	-	0.02
31	मलेशिया	0.21	0.06	0.29	0.12	0.21	1.89